

मुख्य समाचार :-

- उद्यान विभाग उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के सेब की सरकारी खरीद करेगा।
- उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आज समूह 'ग' के विभिन्न पदों पर भर्ती परीक्षा का आयोजन, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
- उत्तराखंड पुलिस ने नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया; हाकम सिंह समेत दो गिरफ्तार।
- राज्य में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 24 सितंबर से पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट प्रक्रिया शुरू होगी।
- राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की।

घोषणा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली गांव और आसपास के क्षेत्रों के सेब की सरकारी खरीद की घोषणा की है। रॉयल डिलीशियस सेब 51 रुपये प्रति किलोग्राम और रेड डिलीशियस व अन्य सेब 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर उद्यान विभाग खरीदेगा। ग्रेड-सी सेब इसमें शामिल नहीं होंगे। इस खरीद के लिए धनराशि मुख्यमंत्री घोषणा मद से उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग को तत्काल कार्रवाई कर शासनादेश जारी करने और प्रगति की जानकारी मुख्यमंत्री को देने के निर्देश दिए हैं।

समूह 'ग' भर्ती परीक्षा

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आज पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी सहित विभिन्न पदों के लिए ग्रुप सी परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं और अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 416 पदों को भरा जाएगा। आयोग द्वारा परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

भंडाफोड़

उत्तराखंड पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षा में पास करवाने का प्रलोभन देने वाले नकल गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना हाकम सिंह सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह और एसटीएफ एसएसपी नवनीत भुल्लर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों से पास कराने के नाम पर 12 से 15 लाख रुपये तक की मांग की जा रही थी। सूचना मिलने पर संयुक्त टीम ने गोपनीय जांच की। इसमें पंकज गौड़ नाम के अभ्यर्थी के संपर्क में हाकम सिंह के होने की पुष्टि हुई। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की गोपनीयता और सुचितता से कोई समझौता नहीं हुआ है। दोनों आरोपियों पर उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण) अध्यादेश 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

अपील

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रीना जोशी ने कहा है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का अपना अलग महत्व है। उन्होंने सभी आयुष्मान सूचीबद्ध अस्पतालों से 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वास्थ्य पखवाड़े में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की है। उन्होंने अस्पतालों से शिविर की तिथि और स्थान तय कर उसका प्रचार करने को कहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम संपन्न होने के बाद उसका विवरण और फोटो पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि जो अस्पताल अपने परिसर में इंडोर कैंप लगाएंगे, उन्हें उस दिन सभी सेवाएं निःशुल्क देनी होंगी। उन्होंने आउटडोर कैंप को ज्यादा प्रभावी बताते हुए दूरदराज क्षेत्रों में प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट प्रक्रिया

राज्य में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए 24 सितंबर से पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद विस्तृत प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा ताकि प्रदेश को विशेष पैकेज मिल सके।

आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में देहरादून में हुई बैठक में जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए कि एसडीआरएफ मद में आच्छादित और अनाच्छादित क्षति का विवरण तुरंत उपलब्ध कराया जाए। श्री सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बंद सड़कों को शीघ्र खोलने, बारिश बंद होते ही पैचवर्क शुरू करने और बिजली-पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अगले हफ्ते से फील्ड विजिट करेंगे और दो दिन जिलों में रुककर पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। आपदा के बाद आवश्यकताओं के आकलन के लिये भारत सरकार की चार टीमों बुधवार से प्रदेश में पहुंचेंगी, जिनका नेतृत्व जिलाधिकारी करेंगे।

सचिव ने कहा कि आपदा से प्रभावित लोगों की आजीविका बहाल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पर्यटन, परिवहन, होटल-ढाबे, तीर्थ पुरोहित, किसान, विक्रेता और अन्य व्यवसायों को हुए नुकसान का भी आकलन कर पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट में शामिल किया जाएगा।

समीक्षा-राज्यपाल

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने 15 और 16 सितम्बर को हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का स्थलीय निरीक्षण किया और जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों से आपदा के बाद किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली। जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि आपदा की सूचना मिलते ही प्रशासन ने तत्काल खोज और बचाव कार्य शुरू किए और प्रभावित क्षेत्रों में राहत पहुंचाई। राज्यपाल ने कहा कि ऐसी आपदाओं से सीख लेकर भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करनी होगी। उन्होंने आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने की बात कही। इसके बाद राज्यपाल ने नन्दा की चौकी में क्षतिग्रस्त पुल और बन रहे वैकल्पिक मार्ग का निरीक्षण किया और शीघ्र आवागमन सुचारु करने के निर्देश दिए। उन्होंने टपकेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र का भी दौरा किया, स्थानीय लोगों और पुजारियों से नुकसान की जानकारी ली और कहा कि शासन-प्रशासन के प्रयासों से स्थिति जल्द सामान्य होगी।

कार्यशाला

आईआईटी रुड़की में उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समन्वयकों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। एपीजे अब्दुल कलाम ब्लॉक में आयोजित इस कार्यक्रम में नवाचार, पारंपरिक ज्ञान और उद्यमिता के माध्यम से सतत ग्रामीण विकास पर चर्चा हुई। आईआईटी रुड़की के निदेशक प्रोफेसर कमल किशोर पंत ने ग्रामीण सशक्तिकरण में तकनीक और नवाचार की भूमिका पर ज़ोर दिया। पद्मश्री सेठपाल सिंह ने कृषि में विविधता और पारंपरिक ज्ञान के महत्व को रेखांकित किया। तकनीकी सत्रों में कृषि विविधीकरण, शहद प्रमाणीकरण, जैविक खेती, मौसम पूर्वानुमान और उद्यमिता जैसे विषयों पर विचार रखे गए। इस दौरान प्रतिभागियों ने आईआईटी रुड़की की एग्रोमेट वेधशाला का दौरा किया और कृषि नवाचारों का अनुभव लिया।

जीएसटी शिकायत निवारण

उपभोक्ता कार्य विभाग ने अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सोमवार से प्रभावी संशोधित जीएसटी दर और छूट लागू होने के बाद उपभोक्ताओं की संभावित शिकायतों के समाधान के लिए एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र-आईएनजीआरएम पोर्टल पर एक नई सुविधा शुरू की गई है। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1915 पर सत्रह भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

बहुउद्देशीय शिविर

डोईवाला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कल 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान के अंतर्गत बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और नगर पालिका अध्यक्ष ने संयुक्त रूप से किया। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञ विभागों द्वारा कुल 599 लोगों की स्वास्थ्य जांच और परामर्श प्रदान किया गया।

शिविर में रक्तदान और दिव्यांगजन सहायता शिविर भी आयोजित किए गए। जनप्रतिनिधियों ने रक्तदान कर अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र और आवश्यक सामग्री वितरित की गई। इस दौरान अतिथियों ने स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की सराहना की और केंद्र को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।